Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2016 = 6.17, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.49366, MAR–APR, 2018, VOL- 5/44

आंतरिक सुरक्षा के लिए मीडिया की सशक्त भूमिका

हेमन्त कुमार पाण्डेय, Ph. D.
सह आचार्य, रक्षा अध्ययन विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.)

Abstract

किसी भी देश की तीन आधारभूत संपदायें होती हैं– पहली–जनता यानी देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, बोलियों, मूलवंश, क्षेत्रीयता से जुड़े, विभिनन संस्कृतियों से संबंधित करोड़ों लोग जो इस देश की समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, विकास संबंधी स्थिति के अभिन्न भाग हैं। दूसरी–भौतिक संपदा जैसे प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा–प्रतिरक्षा–शोध–संचार के केन्द्र, उद्योग धंधे, महत्वपूर्ण स्थान–संसद, विधानसभाए, मंत्रालय, वी.वी.आई.पी. लोग व उनके आवास, मॉल, स्टेडियम, लोगों की बड़ी संख्या वाले सार्वजनिक स्थान, धार्मिक आस्था के केन्द्र सहित अन्य अनेक संपदायें। और तीसरी संपदा है–सूचनाएं, यानी देश से जुडे गुप्त राज़, देश के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, देश की आर्थिक, प्रतिरक्षा, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जिनका कोई अन्य देश कूटनीतिक लाभ उठा सकता है।

मुख्य शब्द *:– आंतरिक सुरक्षा , मीडिया*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना :–

अबूझमाड़ के हर्राकोडेर में पुलिस एवं नक्सलियों की मुठभेड़ में मारे गये एक नक्सली के मुस्लिम होने की खबर एक अखबार में आयी। इसी खबर में उल्लेख किया गया था कि इससे पूर्व 2006–07 में बस्तर में आयोजित नक्सल काँग्रेस में कश्मीरी उग्रवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के पतिनिधियों के शामिल होने की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई थी, कुछ अरसा पूर्व नक्सलियों की केन्द्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने भी बयान जारी कर उग्रवादियों से नक्सलियों के साथ मिलकर लड़ने की अपील की थी। वहीं एक और खबर कहीं पढ़ने में आयी थी कि नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में जो नक्सली समूह सक्रिय हैं उनमें से कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा गया है।

इससे पहले कुछ ऐसी खबरें आयीं थीं कि श्रीलंका के लिट्टे के बचे खुचे उग्रवादियों में से कुछ द्वारा नक्सलियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नक्सली मुठभेड़ों के बाद की तलाशी में चीनी हथियारों का मिलना भी सुधि पाठकों को याद होगा।

हाल ही में अलक़ायदा के चीफ़ अयमान अल जवाहिरी ने एक टेप जारी कर बयान दिया था कि बहुत जल्दी अलक़ायदा की भारतीय शाखा शुरू की जाएगी जो भारत में इस्लामिक राज्य का प्रसार करेगी और फिर कहीं समाचार में पढ़ा कि पाकिस्तान के अमीर उमर नाम के किसी व्यक्ति को उस

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शाखा का प्रमुख बनाया गया है। ये खबरें महज़ खबरें नहीं हैं इनके गंभीर निहितार्थ हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रति एक बहुत बड़े ख़तरे की ओर संकेत करती है। नक्सलियो तथा इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों–हिज़्बुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसे संगठनों के आपसी गठजोड़ से देश की सुरक्षा के लियेबड़ा ख़तरा उत्पन्न हो सकता है। नक्सलियों और आतंकवादियों की कार्यप्रणाली, मुद्दों और प्राथमिकताओं में अंतर भले ही हों लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है–भारत को तबाह करना, छिन्न भिन्न करना।

अध्ययन का लक्ष्य :–

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के चलते या अन्य कारणों से कोई भी देश जब आमने सामने से युद्ध नहीं छेड़ पाता तो वह अपने शत्रु देश की इन तीन संपदाओं को प्रभावित कर उसे कमज़ोर करने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं जिससे देश की व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता, संघवाद के प्रति जनता का विश्वास डोल जाए और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जनता धर्म, जाति, संप्रदाय, विकास–अविकास, नये राज्य, शोषण, क्षेत्रीय असंतुलन, स्वायत्तता, भाषावाद जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलित हो जाती है। सर्वत्र अशांति और अविश्वास की स्थिति निर्मित हो जाती है। साधारण सा प्रतीत होने वाला धरना कब हिंसक विद्रोह बन जाता है पता ही नहीं चलता। इस स्थिति को विघटन कहा जाता है।

देश की महत्वपूर्ण संपदाओं, आधारभूत संरचनाओं, ऊर्जा–संचार–प्रतिरक्षा–शोध, धार्मिक केंद्रों, लोकतात्रिंक स्थानों पर मानव बम, आई.ई.डी. ब्लास्ट या आतंकी हमले करके जब उन्हें क्षति पहुंचाई जाती है या नष्ट किया जाता है तो उसे हम विध्वंसात्मक गतिविधि कहते हैं। और जब देश से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं, रहस्य, गोपनीय नीतिगत निर्णयों आदि को जानने की कोशिश की जाती है तो उसके लिये शत्रु देश की गुप्तचर एजेंसियाँ अपना एक जासूसी तंत्र तैयार करती हैं। देश के वैज्ञानिकों, ब्यूरोक्रेट्स, सैन्य अधिकारियों, डिप्लोमेट्स तथा अंदरूनी सूचनाओं तक पहुंच रखने वाले महत्वपूर्ण लोगों को जासूसी के जाल में फंसाया जाता है और उनका दोहन किया जाता है। किसी से छुपा नहीं है कि देश में किसी भी मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। देश में संसद, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद सहित अनेक स्थान आतंकी हमलों और बम विस्फोटों के शिकार हुए हैं। देश कई शीर्षस्थ अधिकारियों, नौकरशाहों, सैन्य अधिकारियों पर जासूसी के आरोप लग चुके हैं। कुल मिलाकर यह साफ है कि भारत के दुश्मन भारत की इन तीनों ही संपदाओं के प्रबल शत्रु हैं और भारत को पूरी तरह से बरबाद कर देना चाहते है। ये सारी लड़ाईयाँ हिन्दुस्तान की सरज़मीन पर हो रही हैं न कि सीमायी मोर्चे पर।

आज भारत की सीमाओं की जो स्थिति है और पड़ोसी देशों सहित विश्व के अन्य देशों से भारत के जो संबंध है उनके मद्देनज़र एक बात स्पष्ट है कि भारत की सीमायी रक्षा और आंतरिक

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सुरक्षा अब दो अलग–अलग विषय नहीं है बल्कि एक ही विषय है– राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकार। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये मौजूदा खतरों और संभावित नई चुनौतियों पर विचार करने के लिये हमें पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र पर दृष्टि डालनी होगी। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांलग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं जिनमें पूरी दुनिया की लगभग 1/6 आबादी निवास करती है। यह पूरा इलाका विकासशील और गरीब देशों का इलाका है जहाँ प्रजाति, धार्मिक और भाषायी घालमेल के चलत विघटन, आतंकवाद और विद्रोहों से प्रभावित रही है। यह ध्यान रहे कि इन सभी देशों की सरहदें भौगोलिक या प्राकृतिक नहीं हैं, दो देश आप में मूल प्रजाति के आधार पर भी पृथक नहीं किये जा सकते, भाषाएं भी साझी हैं, संस्कृतिया भी साझी हैं, इसी का लाभ देश के दुश्मन उठाते हैं। साथ ही जो सीमाएं हैं वे राजनीतिक आधार पर बनाई गई सीमाएँ ह और भारत इस क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका में है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी से निकले हैं, वहीं नेपाल, भूटान और श्रीलंका का भारत से गहरा नाता रहा है। इन सभी देशों का सामाजिक ताना बाना, संस्कृति, भाषा बोली, खान–पान, धर्म जैसी तमाम बातें सरहदों की बंदिशों से परे हैं।

दक्षिण एशिया न केवल जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहा है, बल्कि अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, आवास, भोजन जैसी आधारभूत समस्याओं से भी जूझ रहा है, इसके बावजूद ये देश भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। अवैध धन का प्रवाह, हवाला कारोबार फैला हुआ है। इसी दक्षिण एशिया में अफीम, चरस, हेरोइन, हशीश जैसे नशीले पदार्थों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। नशीले पदार्थों की स्मगलिंग और आतंकी गतिविधियों के गठजोड़ के कारण इस पूरे क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष का वातावरण निर्मित हुआ है। इसके चलते नाका टेररिज्म का उदय हुआ है। इससे भारतीय पृष्ठभूमि भी पृथक नहीं है।कश्मीर–कश्मीरी आतंकवादियों और पाकिस्तानी शह से त्रस्त है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर तक पाकिस्तान की सरहद लगती है जहाँ से न केवल नशीले पदार्थों, हथियारों, विस्फोटकों की स्मगलिंग होती है बल्कि सीमायी इलाकों में विघटन की भी सारी कोशिशें की जाती ह। नॉर्थ–ईस्ट में अलगाववादी ताकतें उग्रवाद और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की आड़ में पनप रही हैं। बांग्लादेश से लगी सीमा से घुसपैठिये तथा शरणार्थियों का आना बंद नहीं हुआ है जो लोग देश में विभिन्न जगहों पर फैल गये हैं और नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने जमीनों पर कब्जा करके और सस्ता श्रम उपलब्ध कराके स्थानीय लोगों से संघर्ष भी किया है। उत्तर पूर्व में ही ड्रेगन (चीन) अपना दबदबा बनाये हुए है जो अरूणाचल प्रदेश, अक्साईचिन पर अपना हक बताता है, हमारी सीमाओं में घुस आता है। श्रीलंका और भारत के बीच तमिल ईलम का विषय है, जिस आग ने देश के एक श्रेष्ठ नेता की बलि ले ली है। देश में माओवादी पशुपति से तिरूपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। देश के कई राज्य आज नक्सलवाद की चपेट में आ गये हैं और नक्सली विस्तार करते जा रहे है, देश विरोधी अन्य ताकतों से दुरभिसंधियाँ कर रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये विघटन सबसे बड़ा खतरा

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

है। देश में जनता के विघटन यानी सबवर्शन का सबसे बड़ा कारण है, इसकी विविधता, जो देश की आतंरिक सुरक्षा के एक खतरनाक पहलू की आर इशारा करता है।

भारत में सैकड़ों भाषाओं–बोलियों, हजारों समुदाय, दर्जनों प्रजाति मूल एवं जातियों, धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं जिनके आपस में टकराने के कई कारण इन्हीं के बीच मौजूद हैं। अंग्रेजों ने इसी विविधता का लाभ हमें विभाजित करने के लिये उठाया और अब पाकिस्तान, चीन सहित अन्य शक्तियाँ जो भारत पर किसी न किसी रूप में बढ़त या दबाव बनाना चाहती हैं, इसका लाभ उठा रही हैं।

विगत दशको में खासकर आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद व्यवसाय और राजनीति में पैसों का प्रभाव और प्रवाह जोरदार तरिके से बढ़ा है जिसके चलते देश में कस्बों तक में करोड़पतियों का उदय हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुध दोहन, औद्योगीकरण, गंदी बस्तियो का विस्तार, विस्थापन, स्थानीय समुदायों की भावनाओं का दोहन, पावर पॉलिटिक्स, खरीद फरोख्त की राजनीति, प्रशासनिक तंत्र पर हावी होने की कोशिशें, मीडिया की ताकत का नाजायज़ प्रयोग बढ़ा है वहीं राष्ट्रीय एकता ऊपर से तो ठीक ठाक दिखती है लेकिन भीतर से कहीं दरक गई है, संघीयता की दृष्टि का भी अवमूल्यन हुआ है। इससे केंद्र–राज्य संबंधों पर भी असर पड़ा है। देश में शासन तंत्र कमजोर पड़ा है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, बहुदलीय व्यवस्था, वोटों की और चुनावी राजनीति ने देश में आंदोलनों और अशांति को और बढ़ावा दिया है। देश में विभिन्न समुहों में परस्पर अविश्वास और असुरक्षा की भावना ने जन्म लिया है। विभिन्न जातियों, समुदायों, धर्मों की भावात्मक संवेदनशीलता से खिलवाड़ आसान हो गया है। वहीं असमान विकास और जन अपेक्षाओं के पूरा नहीं होने से लोग वंचित महसूस करते हैं। लोगों में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा देश के विघटन का एक प्रमुख कारण है। पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें भारत के ऐसे ही लोगों को अपना निशाना बनाती है जिनका इन सभी कारणों से कानून–व्यवस्था देश के संविधान तथा देश के तंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया है। चीन की भूमिका भी देश में आंतरिक अशांति पैदा करने में है। यह स्थापित तथ्य है कि चीन ने नगा, मिज़ो तथा मीति अतिवादियों को आर्थिक मद्द, हथियार तथा सुरक्षित अभ्यारण्य उपलब्ध कराये ह। पाकिस्तान से क्षेत्रीय दुरभिसंधि की, सैन्य तकनीक–न्यूक्लियर टेक्नॉलॉजी दी, पाकिस्तान, म्यांमार तथा बांग्लादेश से गठजोड़ के प्रयास किये हैं तथा भारत पर दबाव बनाया हुआ है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद और भारत विरोधी रुख पाकिस्तान की विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है इसीलिये आई.एस.आई. भारत की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न भिन्न करना चाहती है।

इस तरह आतंकवाद, नक्सलवाद, उत्तर पूर्व के उग्रवाद, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीयता की भावना के ह्रास जैसे कारणों ने देश में आंतरिक सुरक्षा के लिये बड़ी चुनौती पेश की हुई है। तिस पर सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोगों में इसे लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है।

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सूचना तकनीकी की क्रांति ने बाहरी ओर आंतरिक सुरक्षा के लिये बड़ी चुनौतियाँ खड़ीकी हैं। इंटरनेट के जरिये उत्तेजक सामग्री से लेकर बम बनाने की विधि तक की सारी बातें सहज उपलब्ध हैं। किसी विघटनकारी तत्व को अब भौतिक रूप से किसी टारगेट एरिया में पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट, वीडिया–कॉफ्रेंसिंग के जरिये विश्व के किसी भी कोन से बैठकर किसी भी कोने में या दुनिया भर को संबोधित किया जा सकता है और पाक समर्थित अतिवादी संगठनों आर आई.एस.आई द्वारा इसका भरपूर दोहन किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इन संगठनों, समूहों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ विषवमन किया जाता है, भड़काऊ लेख, टिप्पणिया दिये जाते हैं, कपोल कल्पित भड़काऊ बातों को बिजली की तेजी के साथ शेयर कर माहोल को प्रभावित किया जाता है। विगत समय में फेसबुक और वॉट्सएप के चलते कई स्थानों पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

वहीं इस क्रांति से आये परिवर्तनों ने ग्लैमर वर्ल्ड को खूब लोकप्रिय बना दिया है, आज आम देशवासी का समय टी.वी. सेट्स के सामने, इंटरनेट या मोबाईल पर खर्च हो जा रहा है जिससे लोगों का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की ओर से हटा हुआ सा महसूस होता है। देश की आंतरिक और बाह्या सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस, सशस्त्र बलों तथा देश की सेनाओं का ही नहीं है, बल्कि हर देशवासी का है।

निष्कर्ष :–

केंद्र और राज्य की सरकारों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये मौजूदा खतरों से निपटने के लिये कई उपाय करने की कोशिशें की हैं जिनमें ज्वाइंट ऑपरेशन, मल्टी एजेंसी सेंटरों का विकास, नेशनल डिजास्टर मैंजेजमेंट, इंटेलीजेंस शेयरिंग जैसे अहम कदम तो हैं ही साथ ही पुलिस और सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण के लिए, प्रशिक्षण, संसाधनों की व्यवस्था के लिये भी प्रयास हो रहे हैं। ये सभी कोशिशें अपने आप में तब तक सफल नहीं होगी जब तक इस देश की सबसे बड़ी ताकत देश की जनता जागरूक नहीं होगी। जनता को अपने आस पास घट रही घटनाओं पर नजर रखनी चाहिये। कौन सी घटना किसी बड़े राष्ट्रीय संकट का कारण बन जाए कोई नहीं जानता। हमें अपने आसपास के संदिग्ध और असामाजिक तत्वों को कानून के शिकंजे में लाने में मदद करनी होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली या प्रभावित करने वाली कोई भी बात तुरंत सरकारों की जानकारी में लानी होगी, सुरक्षा एजेंसियो को सहयोग करना होगा। अफवाहें फैलाने वालों का पर्दाफाश करना, भड़काऊ लोगों की पहचान करना, धार्मिक–जातीय–सांप्रदायिक सहिष्णुता को बनाये रखना जरूरी होगा। पीत पत्रकारिता करने वाले मीडिया के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाना होगा। भ्रष्टाचारियों का कड़ा बहिष्कार करना होगा, उन्हें सींखचों के पीछे भेजने में मदद करनी होगी। समाज में विघटन पैदा करने वाले स्वार्थी तत्वों को भी पहचानना होगा और उन्हें कुत्सित खेल करने से रोकरना होगा, तब कहीं जाकर देश विकास के पथ पर अबाध रूप से बढ़ सकेगा और देश सुरक्षित रह पायेगा।

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स्रोतः–

अशोक कुमार : राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली पृ. 18 , सं. 2007

डॉ.डी.एन.सिंह : राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकप्रिय प्रकाशन , मेरठ पृ. 35 अगस्त 2006

डॉ. परशुराम गुप्त : गुरिल्ला युध्द कर्म, पृं. 59 , सं. 2003

रक्षार्थ– वॉल्यूम – 1 नं.2

इंण्डिया टडे , सितम्बर 2006, पृ. 22

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली2007

हिन्दुस्तान, लखनऊ 2009

विचार सारांश अगस्त 2006, पृ. 4–5

डॉ. एल.जे. सिंह – राष्ट्रीय सुरक्षा , सं. 2008

जे.एन.दीक्षित , द फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, साउथ एशियन सर्वे 8 : 1 (2001) सेज पब्लिकेशन , नई दिल्ली पृं.सं. 133

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies